आफरी में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पोषित नर्सरी तकनीक पर विविध हितधारकों हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट

Report on Three Days Training Program on "Nursery Techniques for Arid and Semiarid Tree Species" for others Stakeholders funded by MoEF&CC, Govt. of India

(9 से 11 अक्टूबर 2024)

भावाअशिप- शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जोधपुर (आफरी) द्वारा अन्य हितधारकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम **9 से 11 अक्टूबर 2024** की अवधि में आयोजित किया गया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का विषय "शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र की प्रजातियों के लिए नर्सरी तकनीकी" विषय पर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि आर.के.जैन, मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान वन विभाग द्वारा किया गया। अपने उद्बोधन में श्री जैन ने पश्चिमी क्षेत्रों हेतु ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री नवीन नर्सरी तकनीकों के प्रयोग द्वारा तैयार करने पर जोर दिया तथा इस प्रशिक्षण को सभी प्रशिक्षणार्थियों के लिए उपयोगी बताया। संस्थान के निदेशक डॉ. तरुण कान्त ने अध्यक्षीय उद्बोधन में बताया कि पश्चिमी क्षेत्र में हो रहे पर्यावरणीय असंतुलन की रोकथाम हेतु गुणवत्तापूर्ण पौधारोपण आवश्यक है इसलिए नर्सरी प्रौद्योगिकी का ज्ञान एवं प्रशिक्षण से ही पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है।

इसके पश्चात डॉ संगीता सिंह, समूह समन्वक (शोध) एवं कोर्स समन्वयक ने कार्यक्रम का परिचय एवं रूपरेखा बताई। कार्यक्रम के तकनीकी सत्र में डॉ संगीता सिंह, वैज्ञानिक-एफ ने संस्थान की अनुसन्धान परियोजनाओं एवं डॉ. नवीन कुमार बोहरा, वैज्ञानिक-डी ने ‘‘नर्सरी के लिए बीजों का चयन, बीज भंडारण और बीज अनुकुरण तकनीक’’ विषय और डॉ. बिंदु निर्वाण, बीज अधिकारी, जोधपुर ने ‘‘कृषि वर्ग में बीज भण्डारण की तकनीक’’ विषय पर पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये। प्रशिक्षणार्थियों ने सीड लैब तथा आफरी मॉडल नर्सरी का भ्रमण किया, जहाँ सादुल राम देवड़ा ने नर्सरी तकनीक का व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया।

प्रशिक्षण के दुसरे दिन डॉ. इल्हाम बानो, वैज्ञानिक "बी" ने कैर के नर्सरी तकनीक, डॉ. शिवानी भटनागर, वैज्ञानिक-ई ने "नर्सरी में लगने वाले रोग और कीट", डॉ. नीलम वर्मा, मुख्य तकनीकी अधिकारी एवं डॉ. संगीता सिंह वैज्ञानिक-ऍफ़ ने "जैव उर्वरक और नर्सरी में इनका प्रयोग" तथा श्री राजेश कुमार गुप्ता, मुख्य तकनीकी अधिकारी ने "नीम-पत्ती से खाद बनाना और उसका मूल्यवर्धन" विषय पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किये। प्रतिभागियों ने श्री करनाराम चौधरी, मुख्य तकनीकी अधिकारी, के नेतृत्व में लुणावास अवक्रमित पहाड़ी क्षेत्र का दौरा कर राजस्थान की विलुप्त होती प्रजातियों का पौधारोपण एवं उनका वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में जानकारी हासिल की।

तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन 11 अक्टूबर 2024 अपरान्ह पश्चात् सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉ. जे.पी. मिश्रा, निदेशक अटारी , जोधपुर, ने अपने उद्बोधन में क्लीन प्लांट सिद्धांत को बताते हुए गुणवत्ता पौध चयन एवं इस हेतु प्रशिक्षण के साथ ही फील्ड में प्रायोगिक कार्य हेतु अधिक समय देने की आवश्यकता को बताया। आफरी निदेशक डॉ. तरुण कान्त ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त नर्सरी तकनीक एवं जानकारी को अधिकाधिक अपने-अपने क्षेत्रों में विस्तारित करने का आव्हान किया जिससे वर्तमान जलवायु परिवर्तन से होने वाले दुष्प्रभावों को जन सहभगिता से रोका जा सके। इससे पूर्व डॉ. संगीता सिंह द्वारा "दीमक के प्रबंधन पर एंटोमोपैथोजेन की भूमिका" विषय पर एक व्याख्यान प्रस्तुत किया और साथ ही संस्थान द्वारा निर्मित खेजड़ी पर बने एक लघुवृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों दिए गए व्याख्यान, विभिन्न प्रयोगशालाओं के साथ आफरी के निर्वचन केंद्र के भ्रमण को बहुत ज्ञानवर्द्धक बताया। आफरी द्वारा सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र के साथ उन्नत किस्म का पौधा प्रदान किया गया। कार्यक्रम में आफरी की डॉ. संगीता सिंह, समूह समन्वयक (शोध) एवं पाठ्यक्रम निदेशक ने धन्यवाद किया। कार्यक्रम का संचालन कुसुम परिहार, एसीटीओ ने किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्रगतिशील किसान, गैर सरकारी संगठन, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि एवं छात्र समूह के साथ उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
द्वारा वित्त पोषित अन्य हितधारकों के लिए
तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम
9 से 11 अक्टूबर, 2024
भावाअशिप - शुष्क वन अनुसंधान संस्थ

शुष्क वन अनुसंधान संस्थान
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद